

साय सरकार के 2026-27 के संकल्प आधारित तीसरे बजट में

रायगढ़ जिले के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का संकल्प-आधारित बजट प्रस्तुत किया। सुशासन की प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत यह बजट नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार के पंचतत्वों पर आधारित है। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 'छत्तीसगढ़ अंजोर-2047' के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में इसे एक दूरदर्शी और परिणाममुखी कदम माना जा रहा है।

प्रदेश सरकार का यह तीसरा बजट है। पहले बजट में ज्ञान की आधारशिला रखी गई थी, दूसरे में

विकास की गति को तीव्र करने की रणनीति प्रस्तुत की गई और अब तीसरा बजट समृद्ध एवं खुशहाल छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्पष्ट संकल्प लेकर आया है। इस बजट में रायगढ़ जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे जिले के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश :

बजट में प्रदेश के पांच शासकीय महाविद्यालयों में उच्चकृता केंद्र स्थापित करने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें रायगढ़ भी शामिल है। जिले के प्रतिष्ठित किरोडमल शासकीय महाविद्यालय को 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा



की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में नवीन सीजीआईटी (छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अन्य पिछड़ा वर्गों की छात्राओं के लिए रायगढ़ में 100-100 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। यह पहल बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ सुरक्षित एवं

सुलभ आवास सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

अधोसंरचना परियोजनाओं से विकास को गति: प्रदेश में बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बजट में शामिल किया गया है। रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे तथा खरसिया से परमात्मक रेलवे लाइन जैसी परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को नई दिशा देंगी। इन परियोजनाओं से रायगढ़ सहित पूरे अंचल में आवागमन सुगम होगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

सामाजिक सरोकारों को सशक्त आधार: रायगढ़ के पंडरीपानी क्षेत्र में 100 सीटर दुग्ध एवं श्रवणबाधित विद्यालय तथा छात्रावास निर्माण के लिए 6 करोड़

रुपये का प्रावधान किया गया है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा और आवास की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करेगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में नशामुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल सामाजिक सुधार, जनजागरूकता और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो वर्ष 2026-27 का यह बजट रायगढ़ को शिक्षा, अधोसंरचना और सामाजिक विकास के नए आयाम प्रदान करने वाला साबित होगा। यह बजट जिले को विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

समाचार संक्षेप

आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों से ग्रामीणों में बढ़ रही जागरूकता

430 ग्रामीणों का किया गया निःशुल्क उपचार



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 फरवरी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार तथा जिला आयुष अधिकारी डॉ.सी.एस. गौराह के मार्गदर्शन में शासकीय आयुर्वेद औषधालय बुनागा द्वारा गांव-गांव में आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद पद्धति के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ निःशुल्क उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। औषधालय बुनागा के डॉ. अजय नायक द्वारा विभिन्न ग्रामों में शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया।

शिविरों में मुख्य रूप से वात रोग, उदर रोग, कास (खांसी), चर्म रोग, उच्च रक्तचाप (बीपी), कमजोरी आदि से पीड़ित मरीजों का उपचार कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। फरवरी माह में नावापारा (ब), बोन्दा, रायपाली, बरपाली, शंकरपाली, रनभाठा, पुस्तवा एवं सेमीभावर में शिविर आयोजित किए गए, जिनमें कुल 430 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। डॉ. जागृति पटेल द्वारा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को जीवनशैली जनित रोगों, संतुलित आहार-विहार, योगासन, स्वच्छता एवं नशामुक्ति के संबंध में पाप्यलेट के माध्यम से विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

एक नजर

नगरी ब्लॉक के श्रमिकों को मिलेगा 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन

धमतरी, 25 फरवरी (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नगरी ब्लॉक के श्रमिकों को अब मात्र 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नगरी नगर मुख्यालय में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के संचालन हेतु स्थल चयन एवं आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था करने के निर्देश श्रम विभाग को जारी कर दिए गए हैं। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सविर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित है। वर्तमान में यह योजना धमतरी के कचहरी चौक में संचालित हो रही है, जहां मंडल में पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सावर्वा द्वारा नगरी ब्लॉक के श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ दिलाने हेतु कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा द्वारा श्रम विभाग को नगरी में श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। श्रमयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा इसे शीघ्र प्रारंभ करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। श्रम पदाधिकारी श्री एन.के. साहू ने बताया कि नगरी ब्लॉक में शीघ्र ही नवीन श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दूरस्थ अंचल के श्रमिकों को 5 रुपये में गरम भोजन की सुविधा मिल सकेगी। प्रतिदिन सैकड़ों श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

धमतरी में मखाना की खेती को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेगी किसानों की आय

धमतरी, 25 फरवरी (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पारंपरिक फसलों के साथ अब मखाना की खेती किसानों के लिए एक नया और लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को फसल विविधीकरण के साथ बेहतर आमदनी का अवसर मिल सके। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में संचालित Central Sector Scheme for Development of Makhana के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को जिले के लिए भौतिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। योजना के तहत तालाब में मखाना खेती (Pond Cultivation) हेतु 96.43 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 71,600 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। वहीं खेत में मखाना खेती (Field Cultivation) के लिए 27.42 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए प्रति हेक्टेयर 52,800 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, बीज चयन, रोगण, फसल प्रबंधन एवं विपणन संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन की सक्रिय पहल एवं उद्यानिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से अब तक जिले की 7 ग्राम पंचायतों-झरती/डांडेसरा (29 एकड़), पीपरखेड़ी (6 एकड़), सरसंगुरी (5 एकड़), राखी (15 एकड़), रंकाडीह (30 एकड़), मोतिमपुर (15 एकड़) एवं सांकरा (25 एकड़)-में कुल 125 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती प्रारंभ की जा चुकी है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरलता बढी

कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने ली अहम बैठक



फैस, पाठ्यपुस्तक और मान्यता संबंधी नियमों का अनिवार्य पालन, उल्लंघन की स्थिति में मान्यता समाप्ति की होगी कार्रवाई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 फरवरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव ने जिले के सभी

आशासकीय विद्यालयों के संचालकों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.राव ने कहा कि सभी निजी विद्यालय अपने यहां लागू गणवेश का नमूना विद्यालय परिसर में प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सत्र 2026-27 में लागू पाठ्यक्रम की सूची भी सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से चप्सा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सूचना पटल पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि विद्यार्थी गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों खूले बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। किसी भी

विद्यार्थी या पालक को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली अधिसूचित फैस का मद्देवार विवरण सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही विभागीय मान्यता एवं संबन्धित बोर्ड की संबद्धता की प्रति भी सार्वजनिक रूप से लगाई जाए, ताकि पालकों को पूरी पारदर्शिता मिल सके।

डॉ.राव ने शिक्षा संहिता के अध्याय-6 की कड़िका 95 एवं 96 के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का चयन करने के निर्देश दिए। चयनित पुस्तकों की सूची संबन्धित बोर्ड से अनुमोदित कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ उसकी एक प्रति

जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराना भी अनिवार्य होगा। कड़िका 97 के तहत स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी विद्यालय अपने नाम से कॉपी या किताबों का मुद्रण नहीं करेगा और न ही किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य करेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय में नियमों के विपरीत स्थिति पाई जाती है तो संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।

जल जीवन मिशन के सभी कार्यों को 31 मार्च तक गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप पूरा करें : कलेक्टर

पूर्ण ग्राम पंचायतों को तत्काल करें हैंडओवर, उदासीनता बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 फरवरी। कलेक्टर सभा कक्ष, रायगढ़ में आज जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक कलेक्टर सह-अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और लंबित तथा प्रगतिरत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रतिभा नवरत्न सहित जिले के सभी विकासखंडों के सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं संबन्धित ठेकेदार उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय योजना जल



जीवन मिशन के अंतर्गत सभी निर्माण एवं स्थापना कार्य 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, सतत स्थल निरीक्षण एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां योजनाओं को नियमानुसार ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया तत्काल सुनिश्चित की जाए। यदि किसी पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय योजनाओं के पूर्ण होने के बाद हैंडओवर लेने में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची जिला

पंचायत सीईओ को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता बरतने वाली पंचायतों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने विभागीय तकनीकी टीम को जल जीवन मिशन के कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ठेकेदारों से एक-एक कार्य की समीक्षा करते हुए विभागीय समन्वय के अभाव में रुके हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि जिले के प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनगणना-2027: एक भी व्यक्ति या परिवार गणना से न छूटे, प्रशिक्षण को जिम्मेदारी से लें अधिकारी-कर्मचारी

जनगणना शुद्धता के साथ पूरा करना है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से समझे : कलेक्टर

■ मकान सूचीकरण 1 से 30 मई 2026 तक, पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संचालित होगी प्रक्रिया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



प्रशासनिक एवं विधिक जानकारी प्रदान की गई। कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने जनगणना कार्य को राष्ट्रीय महत्व का दायित्व बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं की आधारशिला होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और मैदानी कार्य में पूर्ण सावधानी, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने

कहा कि एक भी व्यक्ति या परिवार गणना से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आंकड़े विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण के अंतर्गत 1 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन) किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक भवन एवं मकान का डिजिटल माध्यम से सूचीकरण होगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को



जनसांख्यिकीय एवं अन्य आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। कलेक्टर ने सभी संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक करें और उन्हें सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जनगणना की सफ़लता सूक्ष्म योजना, प्रभावी समन्वय और सटीक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। राज्य मास्टर ट्रेनर श्री अशोक मिश्रा, श्री कैलाश चन्द्र पण्डा एवं श्री शेष प्रसाद पण्डा ने

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की प्रक्रियाओं, मैदानी क्रियान्वयन, तकनीकी पहलुओं तथा कानूनी प्रावधानों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार संपूर्ण प्रक्रिया जनगणना प्रबंधन पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्णतः डिजिटल रूप में संचालित की जाएगी, जिससे डेटा की शुद्धता, पारदर्शिता और त्वरित विश्लेषण सुनिश्चित होगा। जनगणना निर्देशालय द्वारा तहसीलवार सॉफ्ट फ़ैल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र को पूर्व

स्थापित मानचित्र के अनुरूप दर्शाया गया है। तहसील स्तर पर इन फ़ैलों की सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा किसी भी विसंगति की स्थिति में आवश्यक संशोधन कर अद्यतन जानकारी प्रेषित की जाएगी। अधिकारियों को पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया तथा उपस्थित चार्ज अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन, स्व-गणना प्रक्रिया, उत्तरदाता की भूमिका, प्रणाली एवं पर्यवेक्षक के दायित्व, डेटा नैतिकता, गोपनीयता एवं सुरक्षा, मोबाइल एवं वेब एप से संबंधित समस्याओं के निराकरण, समय-सीमा के पालन, जनशक्ति प्रबंधन एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सीएमएस के माध्यम से उपयोगकर्ता पंजीकरण एवं एचएलओ प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

धमतरी, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए संचालनालय, समाज कल्याण विभाग रायपुर, द्वारा निःशुल्क बायोनिक् (कृत्रिम) हाथ वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कोहनी से हाथ गंवा चुके दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बायोनिक् हैंड निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। निजी क्षेत्र में जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपये तक होती है, वहीं उपकरण शासन की पहल पर मात्र हितग्राहियों को बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले के

चयनित हितग्राहियों को राजधानी रायपुर भेजा गया। इनमें भूपेंद्र कुमार ध्रुव (ग्राम बनियाटोरा, विकासखंड मगरलोड), चेतन राम साहू (ग्राम करेली छेटी, विकासखंड मगरलोड), बिसाली राम साहू (ग्राम गुजरा, विकासखंड धमतरी), सोमप्रभा निषाद (ग्राम भटेली, नगर पंचायत भखारा) एवं उचित राम ध्रुव (ग्राम सिलौटी, विकासखंड मगरलोड) शामिल रहे। शिविर में बायोनिक् हाथ लगाने के बाद हितग्राहियों ने खुशी जाहिर की। बनियाटोरा निवासी श्री भूपेंद्र कुमार ध्रुव ने कहा कि बायोनिक् हाथ मिलने से उनके जीवन में नई उम्मीद जगी है और अब वे दैनिक कार्य स्वयं कर सकेंगे।

एक नजर

सड़क दुर्घटना में दो आरक्षकों की मौत



रायपुर, 25 फरवरी। बलौदाबाजार जिले में भीषण सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। झूठी दर जाते समय तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आरक्षक धर्मदर यादव और प्रशांतधर दीवान ने जान गंवा दी। घटना सुबह करीब 11 बजे थाना हथबंद क्षेत्र के उडेली-पोसरी के पास हुई। दोनों जवान एक ही बाइक से झूठी दर के लिए निकले थे, तभी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। आरक्षक धर्मदर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वे वर्तमान में साइबर सेल में पदस्थ थे और ग्राम परसबोड, थाना साजा, जिला बेमतरा के निवासी थे। वहीं गंभीर रूप से घायल आरक्षक प्रशांतधर दीवान को रायपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। वे थाना हथबंद में पदस्थ थे और नवागढ़, जिला बेमतरा के रहने वाले थे।

शंकराचार्य को षडयंत्रपूर्वक फंसाया जा रहा : तिवारी

रायपुर, 25 फरवरी। संदीप तिवारी ने कहा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप लगाना और उत्तर प्रदेश सरकार की चुपकी समझ से परे है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार हिंदू और समान धर्म को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और वही भारत देश में गौ हत्या बंद हो इसके लिए सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं आज उसी का परिणाम है कि उनके खिलाफ षडयंत्र पूर्वक यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप लगाए गए हैं। संदीप तिवारी ने कहा कि देश एवं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल-चरित्र को समझ चुकी है, खासतौर पर अब एक बड़ा हिंदू समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है। गौ माता के मांस का व्यापार करने वालों से चंदा लेने वाली पार्टी सनातन होने की बात करती है और इनके इस रूप को जो वास्तविक सनातनी हैं वो अब समझ चुके हैं। सनातन की बात करने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर चुपकी साधे बैठे हैं जबकि वहाँ लगातार हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है लेकिन देश की केन्द्र सरकार कार्यवाही के नाम पर आज तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं की है।

कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण

रायपुर, 25 फरवरी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज जिला चिकित्सालय पंडरी का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता एवं भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर देखा तथा स्टोर में मौजूद दवाइयों का भौतिक मिलान कराया। कलेक्टर ने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक उपलब्ध दवाइयों की स्थिति की तुलना कर रिकॉर्ड संधारण प्रणाली की जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दवाओं का विवरण रजिस्टर के साथ-साथ कंप्यूटर में भी व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाए, ताकि स्टॉक की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान एकसपायर्ड दवाइयों के संबंध में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्देशित किया कि E&Piered दवाइयों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित एवं विधिवत निभाया गया।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया एसटीपी निर्माण का मुद्दा



रायपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई की बात कही।



गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रश्नकाल के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कहा कि 2 बार संशोधन कर जवाब भेजे गए, पहले 26 बताया गया था फिर संख्या 21 भेजी गई, इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत है। 68 नगरीय निकायों में 96 एसटीपी की स्वीकृति है। इस पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि मरे क्षेत्र में एसटीपी प्लांट को लेकर जानकारी मांगी और हर बार प्रक्रियाधीन होने का जवाब आया। हर बार उत्तर गलत आता है। ये जो गुमराह करने वाले अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए किस तरह के इनाम या सजा का प्रावधान है। मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर कार्रवाई की बात कही।

व्यापार एवं उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ में बना है अनुकूल माहौल : मुख्यमंत्री

रायपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी स्थित बीटीआई मैदान में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।



मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है और पूरे प्रदेश के हित में है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट थ्रीम संकल्प है।

सरगुजा क्षेत्र पर किये गए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र राज्य से भी बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन चार दशक से अधिक समय तक नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र विकास से अछूता रहा।

राजधानीवासी खारून का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर, विधायक राजेश मूणत ने लगाया आरोप

रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा में आज राजधानीवासियों को खारून का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर करने वाले दोषियों अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को धेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि खारून नदी के पास एचटीपी लगाने के लिए सरकारी जमीन को छोड़कर अन्य जगह लगाया जा रहा है। जिसके कारण खारून नदी प्रदूषित हो रही है। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि खारून नदी के पास 81 करोड़ रुपए खर्च कर 75 एमएलडी क्षमता का एचटीपी का निर्माण किया गया है। विंगरी नाला का दूषित जल नाले में बनाए गए पीकअपपर से ओवर फ्लो होकर नदी में प्रवाहित हो जाता है। विंगरी नाला का लाइनिंग एवं अप्रोच नहीं होने तथा फिल्टर की सफाई की समस्या बाधित करने से ओवर फ्लो की समस्या निर्मित हो रही है। विधायक राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि 11 एकड़ शासकीय जमीन में यह प्लांट लगाया जाना था, लेकिन इसे अन्यत्र लगा दिया गया है। ऐसे दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

राजधानी में नहीं रुक रही है शराब की अवैध बिक्री

रायपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही थी। जिसके बाद बार रेस्टोरेंट की समय सीमा कर उन्हें हदियत दी गई थी कि किसी भी तरह से अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर में पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा तस्करी, सूखा नशा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई तो की जा रही है। लेकिन अवैध शराब की बिक्री रुक नहीं रही है। अब सवाल उठता है कि पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी शराब कौंचिया आखिर बड़ी मात्रा में शराब लाते कहां से हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री और कौंचियों (अवैध विक्रेताओं) को बढ़ावा मिलने की खबरों के बीच आबकारी विभाग भी सख्त कदम उठा रहा है। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा ही कौंचियों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है।

राजधानी रायपुर के अमलीडीह (राजेंद्र नगर) की शराब दुकान का ये एक वीडियो है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति बड़े थैले में तय लिमिट से अधिक शराब बड़े बैग भर रहा है, और उसके बाद शराब दुकान के सामने ही भारी भरकम बैग को बेखोफ उठाकर ले जा रहा है। इससे ये साफ समझा जा सकता है कि राजधानी में शासकीय शराब दुकानों से ही कौंचियों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखा होगा कि पुलिस और आबकारी विभाग इसपर क्या कार्रवाई करते हैं।



औषधि पादप बोर्ड उपाध्यक्ष शुक्ला प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन का धरसीवा मण्डल में स्वागत

रायपुर, 25 फरवरी। राज्य आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा औषधि पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला का धरसीवा मण्डल में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मण्डल के देवस्थानों में दर्शन पूजा कर कार्यकर्ताओं से भेंट की। धरसीवा मण्डल के सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी सभी मोर्चा मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। उन्होंने ग्राम तेंदुआ में शीला महामाई माता मंदिर में पूजा से अपना दौरा शुरू किया। चरोदा के शिव मंदिर में अभिषेक पूजा कर धरसीवा के हनुमान मंदिर में पूजा सहित निर्माणधीन मंदिर का अवलोकन भी किया। इस कार्यक्रम में मण्डल अध्यक्ष राकेश यादव नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद साहू मण्डल के महामंत्री दिलीप साहू महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण साहू उपाध्यक्ष कौशल साहू पार्षद मोहन प्रजापति ईश्वर यादव जगमोहन धृतलहर भूपेंद्र कसार दुर्गेश अग्रवाल काशी देवांगन प्रकाश देवांगन अंजलि गुप्ता हेमिन बाई साहू इग्नू साहू कैलाश साहू लाता निषाद पितोष साहू सुरेंद्र शर्मा विजय अग्रवाल



गोपाल अग्रवाल फजिल खान सहित मण्डल एवं नगर पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सहित ग्रामजन उपस्थित रहे। सिलियार में पहुंचने पर मंडल महामंत्री अशोक साहू सरपंच श्रीमती साहू कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा विकास शर्मा वही उसके बाद मंगस सरपंच निषाद उपस्थित रहे। बंगोली मंडल में स्थित मां बंजारी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना कर मातारानी से आशीर्वाद लेकर कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की।

रायपुर, 25 फरवरी। शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण एवं काले डस्ट की समस्या को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के नेतृत्व में हीरापुर स्थित पर्यावरण कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण विभाग की निष्क्रियता और उदासीन रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने घरों में सनी काले धूल से डबके सफेद कपड़े साथ लेकर पहुंचे और उसे दिखाकर यह प्रमाणित किया कि शहर में प्रदूषण की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि यह केवल कपड़ों पर जमी धूल नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का काला सच है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकृष्ण शंकर मेनन ने शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण और काले डस्ट की भयावह स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रायपुर आज प्रदूषण की गिरफ्त में है और जिम्मेदार विभाग आरंभ मूंदकर बैठा है। उन्होंने कहा कि एम्स और मेकहरा के डाटा से यह साबित हो रहा है कि प्रदूषण के कारण लंग कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में श्वास संबंधी



बीमारियों के मरीजों की कतार लंबी होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में दमा की समस्या आम बात हो गई है, जो बेहद चिंताजनक है। यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का गंभीर संकेत है। इस प्रदर्शन में प्रमोद दुबे कुलदीप जुनेजा पंकज शर्मा सुधा सरोज ममता राय हीरेंद्र देवांगन दिलीप सिंह चौहान श्रीनिवास राहुल इंद्रियारा देव कुमार साहू प्रकाश जगत मनीराम साहू प्रशांत

तेंगड़ी गंगा यादव प्रगति वाजपेयी हाजरुन बानो कमल धृतलहर सुजीत सिंह किशन बाजारी नरेंद्र उज्ज्वर अनुराम साहू राजेंद्र साहू गजेंद्र कुमार राजू साहू दीपक चौबे वेंकट कुमार रवि थॉमस ईश्वर चक्रधारी सुखदेव सिंह पम्मी चोपड़ा सोहन शर्मा राज देवांगन सागर टांडी अभिनय दुबे मुन्ना मिश्रा मोहम्मद निराज जगदीप कौशिक दिवाकर साहू आकाश दीवान सुशांत डे रुबल मेहता डूमेंद्र दीप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

टिप्पणी कैट के ट्रिज्म एवं एकल खिड़की के सुझावों को बजट में स्थान देने पर राज्य सरकार का आभार

विजन-2047 की दिशा में सर्वांगीण विकास का बजट : कैट

रायपुर, 25 फरवरी। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जगो, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश की विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी एवं संतुलित बजट है।

'विकसित छत्तीसगढ़' का रोडमैप : चेम्बर

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे राज्य की 3 करोड़ जनता, विशेषकर उद्योग एवं व्यापार जगत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि 21.72 लाख करोड़ का यह दूरदर्शी एवं संतुलित बजट संकल्प की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सशक्त रोडमैप प्रस्तुत करता है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. वैद्य की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। थोरानी ने मुख्यमंत्री साय व वित्त मंत्री वैद्य की अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बजट सुशासन, पारदर्शिता, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करेगा। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने का समर्थक रहता है।

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाला बजट : बृजमोहन

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग महिला, किसान, युवा, उद्यमी को महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। बजट के माध्यम से विष्णु सरकार ने यह साबित कर दिया है कि बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि सरकार की भागीदारी, संपत्ति और विकास की दृष्टि का पूरा दायित्व है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेजी पर जोर दे रही है।



बजट से महिलाओं में निराशा घर चलाना मुश्किल : दीप्ति

रायपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बजट में महिला सुरक्षा व उच्च शिक्षा के नाम पर हवाहवाइयें घोषणा कर भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग को मुगेरीलाल के हसीन सपने दिखाए हैं। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रहीं दीप्ति प्रमोद दुबे ने कहा कि बजट नई बोलत में पुरानी शराब है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गत वर्ष के बजट में जो-जो घोषणाएं की थी उनमें से अधिकतर हकीकत के जमीन पर नजर नहीं आ रही है। इस बार के बजट में सामान्य वर्ग की महिलाएं विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी तरह की कोई योजना या राह नहीं है। हॉस्टल से लेकर शिक्षा तक में सामान्य वर्ग की उपेक्षा की गई है। यह बेहद दुखद है। जब सामान्य वर्ग के हितों व जरूरतों का बजट में समावेश ही नहीं है तो फिर इसे कैसे समावेशी

बजट कहा जा सकता है। दीप्ति दुबे ने कहा कि महिलाओं व आम लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं की गई है। जबकि रात नौ बजे भी लोग आंटी से घर जाने में उदरते हैं। जयसंतभ चौक तक में अपराध हो रहे हैं जबकि इस राजधानी का हृदय स्थल कहा जाता है। दुर्भाग्य है कि इस भीड़भाड़ वाले स्थान पर ही अमरुक्षित महसूस करते हुए हृदय भय में धड़कता है। रविवि से पीपचुट करने के लिए एचओडी नहीं होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों में दस से पंद्रह लाख रुपए खर्चना पड़ता है। बिजली का बिल आसमान छू रहा है। घर का बजट बिगड़ गया है। हर माह खर्च बढ़ रहा है। इस दिशा में भी बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट ने महिलाओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

